पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक याचिका क्षेत्रवाद संख्या-1451/2023

(पीएस मामला सं.-484 वर्ष-2020 थाना-भागलपुर कोतवाली जिला-भागलपुर से उत्पन्न)

- =====
1. रवींद्र कुमार तिवारी उर्फ रवींद्र कुमार तिवारी, पुत्र- स्वर्गीय शिव पुजन तिवारी, निवासी मोहल्ला-अभिरामा कॉलोनी, मायागंज, थाना- बरारी, जिला- भागलपुर
 2. विवेक कुमार तिवारी उर्फ बिबेक कुमार तिवारी, पुत्र- स्वर्गीय जितेंद्र कुमार तिवारी, निवासी- मोहल्ला-सुर्यालोक कॉलोनी, बागबारी, थाना- बाबरगंज, जिला- भागलपुर

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. पुलिस अधीक्षक, भागलपुर
3. उप पुलिस अधीक्षक(सदर), भागलपुर
4. थानाप्रभारी, कोतवाली (बरारी) थाना, भागलपुर
5. विष्णु देव सिंह पुत्र- स्वर्गीय हृदय नारायण निवासी- ग्राम और पोस्ट- नगरपारा, थाना- बिहार, जिला- भागलपुर..

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

=====

प्राथमिकी को रद्द करना-परोक्ष अभिप्राय-आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग-भूमि के संबंध में एक विवाद को आपराधिक अभियोजन का रंग दिया गया है और आपराधिक कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग में, प्राथमिकी सूचना देने वाले द्वारा दर्ज किया गया है-उच्च न्यायालय के पास न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी अदालत या आपराधिक कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की अंतर्निहित शक्ति है-तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, अदालत का कर्तव्य है कि वह मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों को देखे। भारत के संविधान की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए खुद को केवल एक मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच की अदालत में एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखने का अधिकार है-वर्तमान मामले के अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना, याचिकाकर्ताओं के लिए न्याय की विफलता के बराबर होगा क्योंकि वर्तमान विवाद एक दीवानी मामले को जन्म देता है।

संदर्भित मामले:

ii. 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 947 (सालिब @शालू @सलीम बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक याचिका क्षेत्रवाद संख्या-1451/2023

(पीएस मामला सं.-484 वर्ष-2020 थाना-भागलपुर कोतवाली जिला-भागलपुर से उत्पन्न)

- =====
1. रवींद्र कुमार तिवारी उर्फ रवींद्र कुमार तिवारी, पुत्र- स्वर्गीय शिव पुजन तिवारी, निवासी मोहल्ला-अभिरामा कॉलोनी, मायागंज, थाना- बरारी, जिला- भागलपुर
 2. विवेक कुमार तिवारी उर्फ बिबेक कुमार तिवारी, पुत्र- स्वर्गीय जितेंद्र कुमार तिवारी, निवासी- मोहल्ला-सुर्यालोक कॉलोनी, बागबारी, थाना- बाबरगंज, जिला- भागलपुर

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. पुलिस अधीक्षक, भागलपुर
3. उप पुलिस अधीक्षक(सदर), भागलपुर
4. थानाप्रभारी, कोतवाली (बरारी) थाना, भागलपुर
5. विष्णु देव सिंह पुत्र- स्वर्गीय हृदय नारायण निवासी- ग्राम और पोस्ट- नगरपारा, थाना- बिहार, जिला- भागलपुर..

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री रंजन कुमार झा

उत्तरदाता/ओं के लिए: मोहम्मद नादिम सेराज

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

तारीख: 19-01-2024

1. वर्तमान रिट आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राथमिकी, कोतवाली (बरारी) पी एस मामला संख्या-484/2020 दिनांकित 31.08.2020 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसका जी. आर संख्या 3347/2020 है और जिसे भा. दं. सं. की धारा 341,323,379,406,420,504,506/34 के तहत दर्ज किया गया है।

2. सूचनादाता/प्रत्यर्थी सं.-5 की लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी में दर्ज अभियोजन मामला, जिसमें उन्होंने कहा है कि 17.11.2001 को सूचक ने 02 कठ्ठा 10 धुर जमीन खरीदी। याचिकाकर्ता सं.-1 के खिलाफ आरोप यह है कि बिक्री के लिए समझौते में उल्लिखित भूखंड को निष्पादित नहीं किया गया था और इसके बजाय सूचक के पक्ष में एक अलग भूखंड, भूखंड संख्या 79-ए, सेक्टर 11/बी-1, चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी, बागबाड़ी, भागलपुर को निष्पादित किया गया था। समझौते के अनुसार प्लॉट संख्या 52, सेक्टर संख्या 11/बी-1 को चंद्र शेखर आजाद कॉलोनी, बागबाड़ी, भागलपुर में निष्पादित किया जाना था। यह भी आरोप लगाया गया है कि जब सूचक ने याचिकाकर्ताओं से इस बारे में शिकायत की, जिन्होंने सूचक से कहा कि उसे समझौते के अनुसार भूखंड मिलेगा, लेकिन जिस भूखंड पर

सहमति हुई थी, उसे सूचक के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया और सूचक द्वारा भूखंड प्राप्त करने के सभी प्रयास व्यर्थ गए। 26.02.2020 को सूचक और उसका बेटा याचिकाकर्ताओं के कार्यालय गए जहाँ याचिकाकर्ता सं.- 1 अपने भतीजे के साथ अर्थात् याचिकाकर्ता सं.- 2 वहाँ मौजूद थे जहाँ कार्यालय के कर्मचारियों ने सूचक और उसके बेटे को चेतावनी दी और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा और गटर में फेंक दिया जाएगा और विरोध करने पर सूचक और उसके बेटे पर याचिकाकर्ताओं और उनके कर्मचारियों द्वारा हमला किया गया। 1 भार की एक सोने की चेन, चार ग्राम की एक सोने की अंगूठी और नकद 11, 200/- रुपये छीन लिए गए।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान प्राथमिकी गलत उद्देश्य से और आपराधिक कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए दर्ज की गयी है क्योंकि सूचक द्वारा वर्ष 2001 में भूमि खरीदी गई थी और लगभग 19-20 वर्ष बीतने के बाद वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2001 में सूचक के पक्ष में गलत भूखंड हस्तांतरित किया गया था।

4. जमीन के मालिक, जिसने सूचक के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया है, को आरोपी नहीं बनाया गया है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए वर्तमान प्राथमिकी 20 साल के अंतराल के बाद दर्ज की गयी है क्योंकि वर्ष 2001 में सूचक याचिकाकर्ता सं.- 1. चंद्र शेखर आजाद कॉलोनी, बागबाड़ी, भागलपुर में भूमि के एक टुकड़े की खरीद के लिए और याचिकाकर्ता ने केवल सूचक को भूमि की मालकिन श्रीमती कुमकुम से मिलवाया। सूचक और भूमि के मालिक ने प्लॉट संख्या 52, सेक्टर संख्या 02 बी/1 वाली भूमि की खरीद/बिक्री 37,000/- रुपये प्रतिफल राशि के लिए बातचीत की। जिसके लिए 17.11.2001 को बिक्री के लिए एक समझौता तैयार किया गया था। बिक्री के समझौते के अनुसार सूचक को निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान करना था, लेकिन सूचक ने

खुद समझौते का उल्लंघन किया है और उस समय के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया है जिसके लिए भूमि मालिक ने राशि को स्वीकार करने से और बिक्री विलेख निष्पादित करने से इंकार कर दिया। हालाँकि, सूचक के अनुरोध पर भूमि के मालिक द्वारा सूचना देने वाले के पक्ष में प्लॉट संख्या 128 और 130 पर कुछ अन्य प्लॉट हस्तांतरित किया गया था जो अनुलग्नक सं. -3. से स्पष्ट होगा/ बिक्री विलेख 30.01.2003 को पंजीकृत किया गया था और सूचक ने स्थिति को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद अपने हस्ताक्षर किए, अपनी तस्वीर चिपकाई और बिक्री विलेख पर बाएं हाथ की सभी पांच उंगलियों का निशान दिया। सूचक और भूमि मालिक के बीच बिक्री और खरीद के पूरे लेन-देन में-श्रीमती. कुमकुम याचिकाकर्ता सं- 1 तस्वीर में नहीं था। न ही याचिकाकर्ता सं.- 1 गवाह बनाया गया था और न ही उसने बिक्री विलेख पर अंगूठे की छाप/हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सूचक ने बाद में प्रवीण कुमार और अन्य के पक्ष में 15.02.2023 को विषय भूमि की बिक्री के लिए एक समझौता किया।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 5/सूचक और राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह सच है कि मामला बहुत पुराना है और याचिकाकर्ता सूचक के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख में पक्षकार नहीं थे।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और प्राथमिकी का अध्ययन किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सूचक का मुख्य तर्क यह है कि चन्द्र शेखर आजाद कॉलोनी, बागबाड़ी, भागलपुर में प्लॉट संख्या 52, सेक्टर सं.-11/B-1 वाले सूचक के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए सहमत नहीं किया गया था और इसके बजाय एक और प्लॉट उसके पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्राथमिकी में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता भूखंड के मालिक थे और उन्होंने सूचक के साथ किसी भी समय बिक्री के लिए समझौता किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क से यह स्पष्ट है

कि प्लॉट नं. 52, सेक्टर नं. 11/बी-1 को सूचना देने वाले और भूमि की मालकिन श्रीमती कुमकुम के बीच दर्ज किया गया था। लेकिन सूचक समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा और समझौते में निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए भूमि मालिक ने सूचक के पक्ष में चंद्र शेखर आजाद कॉलोनी, बागबाड़ी, भागलपुर में प्लॉट संख्या 52, सेक्टर संख्या 11/बी-1 के बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, सूचक भूमि मालिक से एक और भूखंड खरीदने के लिए सहमत हो गया और उसे भूमि मालिक द्वारा 30.01.2003 पर निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से सूचक के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। यह लगभग 20 वर्षों के अंतराल के बाद सूचना देने वाले ने एक कहानी बनाई कि वह याचिकाकर्ताओं से उनके कार्यालय में मिला जहां सूचना देने वाले और उसके बेटे के साथ याचिकाकर्ताओं और उनके कर्मचारियों द्वारा मार पीट की गयी थी ।

7. मामले की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और पंक्तियों के बीच पढ़ने पर यह न्यायालय आश्वस्त है कि मार पीट की कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है जो याचिकाकर्ताओं को भूमि लेनदेन के कारण परेशान करने के लिए है जो 2001-2003 के बीच हुआ था। इस न्यायालय का मानना है कि भूमि से संबंधित विवाद को आपराधिक अभियोजन का रंग दिया गया है और आपराधिक कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग में प्राथमिकी सूचना देने वाले द्वारा दर्ज किया गया है।

8. गंभीर अपराधों से अलग, ऐसे आपराधिक मामले हो सकते हैं जिनमें नागरिक विवाद का एक भारी या प्रमुख तत्व होता है। परेशान करने और बदला लेने के लिए नागरिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक कानून को लागू करने/लागू करने की प्रवृत्ति है। जहाँ तक आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग का संबंध है, वे एक अलग आधार पर हैं। उच्च न्यायालय के पास न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के

लिए किसी भी न्यायालय या आपराधिक कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की अंतर्निहित शक्ति है।

9. सालिब उर्फ शालू उर्फ सलीम बनाम यू. पी. राज्य और अन्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 947 में प्रतिवेदित मामले में माननिये उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह न्यायालय के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि वह केवल प्राथमिकी/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व प्रकट किया है या नहीं। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले के अभिलेख से उत्पन्न कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों को अभिकथनों के अलावा देखे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करे। न्यायालय को भारत के संविधान की धारा 482 या अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय खुद को केवल एक मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखने का अधिकार है।

10. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अलावा इस मामले के अभिलेख से उत्पन्न परिस्थितियों को उचित सावधानी और सावधानी के साथ देखने पर, मेरी राय में, वर्तमान मामला याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के लिए आपराधिक कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग में दर्ज किया गया है।

11. तदनुसार, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वर्तमान मामले के अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना याचिकाकर्ताओं के लिए न्याय की विफलता होगी क्योंकि वर्तमान विवाद एक दीवानी मामले को जन्म देता है।

12. परिणामस्वरूप, 2020 का प्राथमिकी जिसमें 2020 का कोटवाली (बरारी) पी. एस. मामला संख्या 484 दिनांकित 31.08.2020, जी. आर. संख्या 3347/2020 इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

13. आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।